लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16-31 मार्च 2021 www.haryanasamvad.gov.in अंक-14

"आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं"

: स्वामी विवेकानंद

स्वस्थ हरियाणा सशक्त हरियाणा

3

प्रगति के पथ पर 'म्हारा देस हरियाणा'

5

महिला सम्मान- सशक्तिकरण का मान

7

बजट 2021-22

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्तमंत्री प्रदेश सरकार का दूसरा बजट पेश किया। 'सबका साथ-सबका विकास' मूल मंत्र के निहितार्थ जो बजट पेश हुआ वह निसंकोच 'सबका विश्वास' साधने वाला रहा।

फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पेश किया गया प्रदेश का लेखा-जोखा उम्मीदों पर खरा उतरा। हालांकि बजट आने से पूर्व कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना काल से डगमगाई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस बार हाथ सिकोड़ने वाला बजट रह सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने न केवल टैक्स फ्री बजट पेश किया बल्कि अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर यह संकेत दे दिया कि हरियाणा के विकास का पहिया रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में प्रदेश और सशक्त एवं समृद्ध होगा।

बजट के कुछ मुख्य बिंदू

सेहत

350 चिकित्सा अधिकारी, 60 दंत चिकित्सक की भर्ती होगी। हर सिविल अस्पताल में 200 बेड। 1,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खुलेंगे। आयुष्मान भारत योजना का लाभ आठ और श्रेणियों को, पांच लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों को अनुपातिक आधार पर मिलेगा लाभ। सीएचसी में अल्ट्रासाउंड व अन्य डायग्नोस्टिक सेवाएं। हर जिला अस्पताल में आईसीयू व प्राइवेट रूम। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में कैंसर विज्ञान केंद्र की होगी स्थापना। अनुबंध आधार पर 100 आयुष सहायक व 22 आयुष कोच की भर्ती होगी।

शिक्षा

नौवीं से बारहवीं तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। 4000 प्ले स्कूल खुलेंगे। पहली से तीसरी कक्षा तक के 6 लाख विद्यार्थियों को प्रारंभिक भाषा व गणितीय कौशल सिखाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 700 करोड़ से डिजिटल क्लास रूम व टैबलेट की व्यवस्था। जेंडर इनक्लूजन फंड की व्यवस्था। हिसार, करनाल में भी सुपर 100 कार्यक्रम शुरू होगा। एमडीयू व केयू में केजी से पीजी तक होगी शिक्षा।

किसान

पांच एकड़ प्रति परिवार तक की कुल भूमि वालों को 6,000 रुपए वार्षिक मदद। किसान मित्र, हर खेत, स्वस्थ खेत योजना। 1,000 किसान एटीएम। 125 मृदा परीक्षण लैब। 100 बायो गैस प्लांट। नई सिंचाई परियोजनाएं की घोषणा।

पेंशन

बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी कर इस साल एक अप्रैल से यह पेंशन 2,500 रुपए करने की घोषणा।

रोजगार

50 हजार युवाओं को रोजगार देने का वादा। 2025 तक पांच लाख अति गरीबों की आय 1.80 लाख होगी। वर्तमान में 1.80 लाख रुपए आय वाले परिवारों को 6,000 रुपए सालाना वित्तीय सहायता। दुर्घटना या अनहोनी का शिकार होने पर विस्तृत बीमा कवर। 20,000 आवास की व्यवस्था।

कौशल शिक्षा

पॉलिटेक्निक मानेसर में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में नौवीं से आगे के विद्यार्थियों का फीडर स्कूल, विश्वकर्मा कौशल रथ नाम से मोबाइल आईटी लैब होगी स्थापित। पीएचडी के लिए अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम शुरू होगा। सिकरोना, फरीदाबाद, इंदी, करनाल व जीवननगर सिरसा में तीन नए आईटीआई की होगी स्थापना।

आत्मनिर्भर

सक्षम युवा योजना और प्रभावी होगी। 20 से 35 साल के बेरोजगारों को रोजगार के लिए कौशल विकास की सुविधा। 2025 तक ऊष्मायन केंद्र से 50 प्रतिशत युवाओं को व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी।

खिलाड़ी

पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में हॉकी, फुटबॉल, बॉस्केटबॉल व बॉलीबाल के नए मैदान। पंचकूला में स्थापित राज्य स्तरीय चोट उपचार पुनर्वास केंद्र, मंडल स्तर के चार केंद्र रोहतक, गुरुग्राम, करनाल व हिसार में। ओलंपिक की तैयारी के लिए पांच लाख रुपए प्रति खिलाड़ी अग्रिम सहायता।

बेटियां

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत शादी से पहले या शादी के दिन वित्तीय मदद। पुलिस बल में 15 प्रतिशत हिस्सा।

मुख्य बजट आवंटन

विभाग	प्रस्तावित बजट (करोड़ रुपए में)
शिक्षा	18,410
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	10,798
सिंचाई और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी	8,483
स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र	7,337
बिजली एवं गैर परंपरागत ऊर्जा	7,359
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	6,110
ग्रामीण विकास एवं पंचायत	5,980
शहरी स्थानीय निकाय	3,970
लोकनिर्माण, सड़क और पुल	2,985
परिवहन	2,408
श्रम	1,823
महिला एवं बाल विकास	1,621
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना	824
अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण	524
उद्योग एवं व्यापार	330

कहां से मिलेगा सरकार को रुपया

कहां खर्च होगा रुपया

राजस्व प्राप्तियां प्रस्तावित	87,733 करोड़
राजस्व व्यय प्रस्तावित	1,16,927 करोड़
पूंजी प्राप्तियां प्रस्तावित	39,751 करोड़
पूंजीगत व्यय प्रस्तावित	10,557 करोड़

संपादकीय

बजट प्रबंधन

वार्षिक बजट का यह एक दिलचस्प पहलू है कि प्रत्येक उत्पादक चाहता है कि उसे बाजार में अच्छे दाम मिलें ताकि उसके श्रम से परिवार में खुशहाली आए। दूसरी ओर प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि उसे सभी सुख कम दामों पर मिलें। इन दोनों के मध्य संतुलन बनाना, हर बजट की मुख्य चुनौती होती है।

इसी संदर्भ में दो बातों का विशेष रूप से उल्लेख सार्थक होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में अपनी पत्रिका नवजीवन में दांडी-मार्च का उल्लेख करते हुए 'स्वराज और रामराज्य' की अनूठी व्याख्या दी थी।

इसी में उन्होंने गोस्वामी तुलसी दास कृत दोहावली के कुछ उदाहरण दिए थे। पहला उदाहरण उन्होंने कर व्यवस्था के बारे में राम-भरत संवाद से दिया था। इसमें राम, भरत को करों के बारे में एक तर्कसंगत व्याख्या समझाते हैं। श्रीराम, भरत को सुझाव देते हैं कि करों व बजट प्रबंधन के बारे में हमें सूर्य से सीख लेनी चाहिए।

'सूर्य, नदी, सागर, जोहड़ और सभी अन्य जल-भण्डारों से जल को पहले सोखता है फिर वर्षा के रूप में सूर्य देवता सभी स्थलों एवं प्राणियों को जल प्रदान करता है।' तुलसीदास ने इसे दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है-

'बरसत, हर्षत, सब लखैं
कर्षत लखैं न कोय
तुलसी प्रजा सुभाग से
भूप, भानू सा होय'

इसी तरह तुलसी दास आगे लिखते हैं-

'मणि माणिक महंगे किए
स्हजे तृण, जल, नाज
तुलसी सोई जानिए
राम गरीब नवाज'

अर्थात् समृद्ध लोगों से कुछ अतिरिक्त लेकर कमतर लोगों में जल, तृण, अनाज सस्ता देना ही रामराज्य है।

राम चेतावनी भी देते हैं-

जासू राज, प्रिय, प्रजा दुखारी
ते नृप अवस नरक अधिकारी

ऐसे चुनौतीपूर्ण एवं आपदा-ग्रस्त वातावरण में भी हमारे प्रदेश ने कोरोना के मामले में लगभग 95 प्रतिशत रिकवरी-दर हासिल की है। संक्रमित लोगों को कुशल स्वास्थ्य रेखाएं प्रदान की गई हैं और जरूरतमंद लोगों तक राहत पैकेज, जैसे भोजन, नगदी और अन्य मूलभूत सेवाएं पहुंचाई गई हैं। इसी अभियान में जन-जन की भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिए हरियाणा कोरोना-राहत कोष का भी गठन किया गया है।

इस बार प्रदेश के जन-निर्वाचित प्रतिनिधियों व विभिन्न हित धारकों, संगठनों व विभागाध्यक्षों से भी सुझाव मांगे गए थे। विधायकों व सांसदों से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों को यथासंभव इन बजट प्रस्तावों में शामिल किया गया है। गत वर्ष इन्हीं जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त 527 सुझावों में से 200 को पिछले वार्षिक बजट में शामिल किया गया। इनमें से 71 लागू हो चुके हैं और शेष 129 सुझाव क्रियान्वयन के अंतिम चरण में हैं।

आय और व्यय को संतुलित रखने का कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर एक बार पुनः दृष्टिपात किया तो एक अर्थ दृष्टि भी मिली। श्लोक था-

'व्युष्ट देशकाल मुखानुवर्तन रूप लक्षण परिमाण निक्षेप
भाजनगो पायकैश्च नीवीं समान्येत्'

सरल भाषा में इस सिद्धांत का भावार्थ है कि शासक को निर्धारित तिथियों पर राजकोष में होने वाली विभिन्न प्राप्तियों तथा व्ययों का संकलन करके शेष धन का मिलान करते रहना चाहिए।

- डा चंद्र त्रिखा

पढ़ाई-लिखाई के साथ कौशल प्रशिक्षण

शिक्षा के लिए 18,410 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। परिव्यय में से 9,014 करोड़ रुपए प्राथमिक, 5,899 करोड़ रुपए माध्यमिक, 2,793 करोड़ रुपए उच्चतर और 705 करोड़ रुपए तकनीकी शिक्षा के लिए है।

वर्तमान में राज्य में 35 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, 10 राज्य विश्वविद्यालय, 24 निजी विश्वविद्यालय और 170 सरकारी कॉलेज शामिल हैं। राज्य सरकार ने विशेष रूप से लड़कियों के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में सरकारी कॉलेज खोलने की एक सक्रिय नीति अपनाई है।

आईआईएम रोहतक, एनआईडी कुरुक्षेत्र, सोनीपत में आईआईटी दिल्ली का विस्तार परिसर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मुरथल और एसआईईटी झज्जर, रेवाड़ी, नीलोखेड़ी जैसी विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा,पंचकूला, उमरी, धामलवास (रेवाड़ी), राजपुर (सढ़ौरा) में नए राजकीय बहुतकनीकी संस्थान स्थापित किए गए हैं और वहां कोर्स शुरू हो चुके हैं। सरकार ने राजकीय बहु-तकनीकी संस्थान, मानेसर में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।

सुपर 100 कार्यक्रम के लिए 10 करोड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम भारत के अति प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए सरकारी स्कूलों से प्रतिभा तराशने में सफल रहा है। इसलिए, इस कार्यक्रम का विस्तार दो और केंद्रों-हिसार और करनाल तक किया जाएगा। इस संबंध में 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। राज्य के स्कूलों में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस 50 दक्ष केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें नौ मुख्य कौशलों को समाहित किया गया है। इस वर्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ब्रिटेन के साथ समझौता

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय देश में अपनी तरह का पहला संस्थान है। इसमें 27 नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और नेशनल ओपन कॉलेज नेटवर्क के माध्यम से ब्रिटेन के सरकारी अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग के साथ एक समझौता किया है। विश्वविद्यालय की योजना पी.एच.डी. के लिए अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम संचालित करने की है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति

एसवीएसयू की योजना उद्योगों/संघों के साथ सांझेदारी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति पर पलवल के दुधौला में बनने वाले अपने परिसर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की है। एसवीएसयू द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से दुधौला परिसर में अपने अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी, प्रबंधन अध्ययन एवं कृषि कार्यक्रमों के तहत अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा।

संवाद ब्यूरो

गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

प्रदेश के गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक अनूठी योजना 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' लागू करने जा रही है। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) बनने के बाद प्रदेश में सबसे कम आय वाले एक लाख परिवारों की पहचान की जाएगी।

ऐसे परिवारों की पारिवारिक आय कम से कम 8,000 से 9,000 रुपए मासिक सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों के कौशल विकास पर जोर देगी तथा बेरोजगार सदस्यों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में कार्य करेगी।

परिवार पहचान पत्र बनाने का काम तेजी से हो रहा है। 65 लाख परिवारों में से 54 लाख परिवारों के पीपीपी कार्ड बन चुके हैं। परिवार पहचान पत्र से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचाने में मदद मिलेगी।

मकान की मरम्मत के लिए अनुदान

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने डॉ. बी. आर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को घर की मरम्मत के लिए प्रदान की जाने वाली 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 80 हजार रुपए करने की घोषणा की है। अब इस योजना का लाभ सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अब तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक ही सीमित था।

उन्होंने कहा कि एक अप्रैल, 2021 से बीपीएल परिवारों के लिए वार्षिक आय स्लैब को एक लाख 20 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपए किया गया है। इतना ही नहीं सामाजिक उत्पीड़न के लिए अनुसूचित जाति को दी जाने वाली कानूनी सहायता बढ़ाकर 21,000 रुपए की गई है।

संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना

श्री मनोहरलाल ने कहा कि महान संतों द्वारा दी गई जातिवाद जैसी बुराइयों को दूर करने और सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे के संदेश को जन-जन जक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना की शुरुआत करने जा रही है।

इसके तहत सामाजिक और धार्मिक संगठनों को ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर महापुरुषों की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कम से कम 50 हजार और अधिकतम एक लाख रुपए की वित्तिय सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत नए वित्त वर्ष के लिए 11 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

संवाद ब्यूरो

करनाल में बनेगा आयुर्वेद शोध संस्थान

भारत सरकार ने करनाल में एक महत्वाकांक्षी परियोजना 'कॉमन फैसिलिटी सेंटर' स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस स्वीकृति से राज्य में पारंपरिक आयुर्वेदिक उद्योग को एक बड़ा बुनियादी प्रोत्साहन मिला है।

हरियाणा सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विभाग 'क्लस्टर-योजना' के तहत प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है। राज्य में सूक्ष्म इकाइयों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक दूरदर्शी 'मिनी क्लस्टर योजना' लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 50 से अधिक एमएसएमई-क्लस्टर की पहचान की गई है और उन्हें पूरे हरियाणा में विकसित किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने करनाल में जिस 'कॉमन फैसिलिटी सेंटर' स्थापित करने की मंजूरी दी है उस पर करीब 15 करोड़ रूपए खर्च होंगे। इस सेंटर में 'आर्ट हर्बल एक्सट्रैक्शन प्लांट', शोध एवं विकास सुविधा, एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी जिससे करनाल और उसके आसपास के 200 से अधिक सूक्ष्म और छोटे आयुर्वेदिक उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों को फायदा होगा।

भारत सरकार द्वारा एमएसएमई फ्लैगशिप योजना के तहत अनुमोदित अपनी तरह की यह पहली क्लस्टर परियोजना है। उन्होंने बताया कि यह 'कॉमन फैसिलिटी सैंटर' स्थापित होने से गुणवत्ता वाले आयुर्वेद उत्पादन में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल ने कहा कि देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने में हरियाणा का अहम योगदान रहेगा। उक्त योजना से गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्यात होगा जिससे संबंधित सूक्ष्म एवं लघु इकाइयां और अधिक सशक्त होंगी। 'कॉमन फैसिलिटी सेंटर' की इस परियोजना से 500 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है।

-संवाद ब्यूरो

सलाहकार संपादक :	डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक :	मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम :	संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक, मनोज चौहान
संपादन सहायक :	सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन :	गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट :	विकास डांगी

'सुपर-100' कार्यक्रम को और बेहतर बनाते हुए सरकारी स्कूलों से प्रतिभा तराशने का कार्य तेज किया गया है। इस कार्यक्रम का विस्तार हिसार और करनाल केंद्रों तक किया जाएगा। इस संबंध में 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय देश में अपनी तरह का पहला संस्थान है। इसमें 27 नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। नेशनल ओपन कॉलेज नेटवर्क के माध्यम से ब्रिटेन के सरकारी अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग के साथ एक समझौता किया है।

बजट 2021-22
स्वस्थ हरियाणा सशक्त हरियाणा

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के मकसद से हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। साथ ही, सरकार ने 'आयुष्मान भारत योजना' के लाभ आठ अतिरिक्त श्रेणियों को प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए धनराशि पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इन श्रेणियों में व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पंजीकृत परिवार, निर्माण श्रमिक बोर्ड, हरियाणा के मान्यता-प्राप्त मीडियाकर्मी, नम्बरदार, चौकीदार, विमुक्त घुमंतु जाति, और आजाद हिंद फौज में रहे सैनिक, हिंदी आंदोलन से जुड़े परिवार, द्वितीय विश्व युद्ध और आपातकाल के दौरान जेल गए परिवार शामिल हैं। सरकार इस योजना का लाभ 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को अनुपातिक आधार पर भी देगी।

नए चिकित्सा संस्थान

भिवानी के मौजूदा जिला अस्पताल को अपग्रेड करके डॉ. मंगल सेन मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। इसी तरह, जींद, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जा रहे हैं। इसी तरह, यमुनानगर, कैथल और सिरसा जिलों में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव है जबकि महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में कैंसर विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज, नल्हड़, नूंह में एक डेंटल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला जिलों में छह सरकारी नर्सिंग संस्थान भी स्थापित किए जा रहे हैं।

आयुष्मान जन आरोग्य योजना

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 के आधार पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वर्तमान में 15.51 लाख परिवार पात्र है। अब तक 7.83 लाख परिवारों को कुल 22.96 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके तहत, 2.05 लाख मरीजों को 245.00 करोड़ की राशि वितरित की गई है।

चिकित्सकों की भर्ती

हरियाणा सरकार ने कोविड महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसी कड़ी में सरकार ने 956 नियमित डॉक्टरों और 206 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की है। अब इस वित्तीय वर्ष के दौरान 350 चिकित्सा अधिकारियों और 60 दंत चिकित्सकों के नए पद सृजित किए जाएंगे।

हेल्थ वेलनेस सेंटर

आयुष विभाग के अंतर्गत पूरे राज्य में 1000 'हेल्थ वेलनेस सेंटर' स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इसमें निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, पुनर्वास और व्यापक स्तर की देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। राज्य के लोगों को वेलनेस सेंटर में सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे कि योगशाला, ध्यान, शारीरिक व्यायाम के अलावा दवाओं और परीक्षण व जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुफ्त इलाज योजना

'मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना' के तहत, लोगों को सात तरह की सेवाएं, जैसे कि सर्जरी, प्रयोगशाला परीक्षण, डायग्नोस्टिक्स (एक्स-रे, ईसीजी, और अल्ट्रासाउंड सेवाएं), ओपीडी/इनडोर सेवाएं, दवाएं, रेफरल परिवहन और दंत उपचार सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी जिलों में कैथ लैब, एमआरआई, सीटी स्कैन और डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी तरह, अल्ट्रासाउंड और अन्य डायग्नोस्टिक्स सेवाओं का विस्तार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक किया जाएगा।

सभी हलकों में सड़क निर्माण

भवन एवं सड़कों के लिए बजट में 10,858 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान 650 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों के निर्माण और लगभग 5,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों के सुधार के साथ-साथ 1007.19 करोड़ रुपए की लागत से 11 बाईपास के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी है। सरकार सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से सड़कों के समान विकास पर कार्य कर रही है। वर्ष 2022-23 तक, जहां भी संभव होगा, 6 करम या उससे अधिक के सभी कच्चे रास्तों पर पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग द्वारा इस वित्त वर्ष के दौरान उचाना और बहादुरगढ़ बाईपास का निर्माण किया जाएगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-III के तहत, हरियाणा राज्य को 2500 किलोमीटर सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य आवंटित किया है। इनमें से 688 किलोमीटर लम्बी सड़कों को वर्ष 2020-21 में और 1213 किलोमीटर लम्बी सड़कों को वर्ष 2021-22 में चौड़ा एवं सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। नाबार्ड की वित्तपोषित योजनाओं के तहत 416 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया और 357 किलोमीटर लम्बी सड़कों का कार्य प्रगति पर है।

2021-22 में नाबार्ड की सहायता से विभाग द्वारा 323 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2020-21 में, 253 करोड़ रुपए की लागत से 317 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया और 1009.15 करोड़ रुपए की लागत से 1545 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण आदि करके सुधार किया गया है। हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों पर सभी लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक, 111 रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज (आरओबी/आरयूबी) का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2021-22 में 20 आरओबी/आरयूबी के निर्माण का प्रस्ताव है।

रोज़गार के लिए बड़े निवेश की योजना

हरियाणा में एक लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और पांच लाख रोजगार सृजित करने के लक्ष्य से नई 'हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020' लागू की गई है, जो राज्य की औद्योगिक विकास गाथा को आगे बढ़ाएगी। उद्योग एवं व्यापार के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

एमएसएमई की क्षमताओं एवं योग्यताओं को और बढ़ाने के लिए, यह निदेशालय पांच प्रमुख फोकस क्षेत्रों यानी एयरोस्पेस एवं रक्षा, खिलौना उद्योग, सेवा क्षेत्र, निर्माण एवं औद्योगिक पार्क में हरियाणा की उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेगा, जिसके चलते हरियाणा भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहल में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में अग्रणी राज्य बनेगा।

मेसर्स एटीएल द्वारा आईएमटी सोहना में 7083 करोड़ रुपए के निवेश और 7,000 रोजगार सृजित करने की क्षमता वाला एक मेगा प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए एचएसआईआईडीसी ने 178 एकड़ भूमि आवंटित की है। कम्पनी की आगामी कुछ वर्षों में स्मार्ट फोनस, दो एवं तिपहिया ई-वाहनों सहित उद्योगों के लिए बैटरियों की आपूर्ति करने हेतु 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है।

राज्य की अनुकूल नीतियों के चलते वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षरित 495 समझौतों में से 188 समझौते 24,051 करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्रियान्वित किये गये हैं या प्रक्रियाधीन है और 32,030 लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है। राज्य में 4,119 स्टार्ट अप पंजीकृत हुए हैं, जो पड़ोसी राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में पंजीकृत 'स्टार्ट अप' की तुलना में काफी अधिक है।

सत्र 2021-22 में सिकरोना (फरीदाबाद), इंद्री (करनाल) और जीवन नगर (सिरसा) में 3 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरंभ किए जाएंगे। वर्ष 2020-21 में 470 कैंपस प्लेसमेंट से 8,012 प्रशिक्षुओं को रोजगार दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 21502 मकान कमजोर वर्गों के परिवारों के लिए बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके तहत अब तक 11,267 मकानों का निर्माण करवाया गया है।

प्रगति के पथ पर

'वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ,

संवाद ब्यूरो

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने इस बार के बजट में लोगों की सेहत पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा खेत की खुशहाली, स्तरीय शिक्षा की अनिवार्यता, गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना और खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन जैसी योजनाओं का परिणाम आने वाले दिनों में अवश्यंभावी है। निसंदेह बजट के जरिए चौतरफा विकास का प्रयास हुआ है।

वित्तमंत्री मनोहरलाल ने आने वाले दिनों में युवाओं के लिए बंपर रोजगार उपलब्ध कराने के संकेत स्पष्ट कर दिए हैं। इतना ही नहीं जल संकट दूर करना, महिलाओं को सशक्त करना, हाउसिंग बोर्ड योजना के तहत नए आवास उपलब्ध कराना, बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि करना, स्मार्ट सिटी योजना को विस्तार देना आदि कुछ ऐसी योजनाओं पर फोकस किया गया जिनका निकट भविष्य में सुखद परिणाम देखने को मिलेगा।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने 2 घंटे 40 मिनट में बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने समग्र एवं सर्वांगीण हरियाणा के निर्माण का जिक्र करते हुए बताया कि आगामी वित वर्ष के लिए बजट में 1,55,645 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जोकि 2020-21 के बजट से 13 फीसदी अधिक है।

कृषि बजट में 20.9 प्रतिशत बढ़ोतरी

किसान व खेती से जुड़े कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन, मत्सय पालन सहित सहकारिता विभाग का बजट 20.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 6,110 करोड़ रुपए किया गया है जो चालू वित वर्ष के लिए 5,052 करोड़ था। इसके साथ-साथ आगामी वित्त वर्ष के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को आवंटित किए बजट में भी 75 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जल की महता को समझते हुए हम जल संरक्षण हेतू सूक्ष्म सिंचाई साधनों पर भी अत्यधिक फोकस कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल, ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करने और उनका कल्याण व उत्थान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन-एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन, गुणवत्तापरक आदानों की उपलब्धता, क्षारीय और लवणीय जल-भराव वाली मृदाओं का सुधार, जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण, जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

'हर खेत-स्वस्थ खेत'

इस वर्ष 'हर खेत-स्वस्थ खेत' नामक एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा करते हुए उन्होंने इस अभियान में मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के आधार पर फसल चयन की सुविधा उपलब्ध करवाने पर बल दिया जाएगा। पंजीकृत किसानों द्वारा फसल की बिजाई की विस्तृत जानकारी 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर 9.14 लाख किसानों ने पंजीकरण करवाया है। अप्रैल, 2021 से प्रत्येक एकड़ के मृदा नमूनों के संग्रहण और जांच का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा और आगामी तीन वर्षों में राज्य के पूरे क्षेत्र को कवर किया जाएगा। किसानों को घर-द्वार पर मृदा जांच सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मंडियों व सरकारी भवनों में 17 नई स्थैतिक मृदा जांच प्रयोगशालाएं और 59 मिनी-मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।

'पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड'

हरियाणा में दूध की उपलब्धता 1,142 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जोकि राष्ट्रीय औसत 394 ग्राम के मुकाबले काफ़ी अधिक है। डेरी, पशुपालन और अन्य संबंधित गतिविधियों में लगे पशुपालक किसानों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति के लिए, राज्य के विभिन्न बैंकों द्वारा 8 लाख पशुपालक किसानों को 'पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड' प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में 70 लाख पशुधन है। सरकार ने पशुधन के लिए 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना' का विस्तार करके पशुधन बीमा करने का निर्णय लिया है।

मत्स्य पालन को बढ़ावा

सरकार द्वारा 2021-22 से 2024-25 के दौरान 'प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना' के तहत 1,090 हैक्टेयर लवणता प्रभावित क्षेत्र और 5,000 हैक्टेयर ताजा पानी वाले अतिरिक्त क्षेत्र का विकास किया जाएगा। झींगा कल्चर के लिए लवणता प्रभावित क्षेत्र विकसित करने के लिए 2021-22 में भिवानी के गरवा गांव में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 'प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना' के तहत, वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 10 स्माल फिश फीड मिल प्लांट यूनिट स्थापित की जाएंगी।

फसल विविधिकरण को बढ़ावा

फसल विविधिकरण और भूजल के किफ़ायती प्रयोग के लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना शुरू की गई है। तदनुसार, 97,000 एकड़ क्षेत्र को धान से अन्य फसलों जैसे कि-मक्का, कपास, बाजरा, दालों, सब्जियों, चना और चारा आदि के अधीन लाया गया है। सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन के रूप में या धान से अन्य वैकल्पिक फसलों के विविधिकरण के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान धान के अधीन का क्षेत्र 2 लाख एकड़ कम करने का लक्ष्य है।

'किसान मित्र योजना'

हरियाणा सरकार 'किसान मित्र योजना' नाम से एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना में बैंकों की सांझेदारी में राज्य में 1,000 किसान एटीएम स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा रबी की फसलों-गेहूं, चना, सरसों और सूरजमुखी तथा खरीफ की फसलों-धान, बाजरा, मक्का, मूंग और मूंगफली पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहा है।

सरकार मक्का, सूरजमुखी, मूंग, चना और मूंगफली की खरीद की अपनी नीति को जारी रखते हुए फसलों के विविधिकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना जारी रखेगी। सरकार कृषि उत्पाद के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित कर रही है। इस वर्ष 6.60 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए साइलो का उपयोग किया जाएगा।

बकरी प्रजनन केंद्र होगा स्थापित

सरकार द्वारा राज्य में बेहतर पशुधन और पोल्ट्री रोग डायग्नोस्टिक्स सेवाएं प्रदान करने के लिए हिसार, सोनीपत और पंचकूला में एवियन इन्फ्लूएंजा तथा अन्य पोल्ट्री रोगों के रैपिड और आरटी-पीसीआर डायग्नोस्टिक्स के लिए तीन बायो सेफ्टी लेवल-2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। सरकार द्वारा सभी 1,020 राजकीय पशु चिकित्सालयों का कंप्यूटरीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार बकरियों की नस्ल के आनुवांशिक उन्नयन और गरीब बकरी पालक, किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय व भैंसों की तर्ज़ पर बकरियों के लिए भी कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का विस्तार करेगी। भिवानी के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकार ने गऊ संवर्धन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है।

कंप्रेस्ड बायो गैस तथा बायो मास प्लांट

राज्य सरकार ने खरीफ 2020 से एक संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधिसूचित की है। सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। अलग-अलग किसानों को सब्सिडी पर 10,042 मशीनें प्रदान की गईं और 1,345 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए। इस वर्ष फसल अवशेषों के उपयोग के लिए प्रदेश में पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से 100 कंप्रेस्ड बायो गैस तथा बायो मास प्लांट स्थापित किए जाएंगे।

कृषि तथा किसान विभाग की योजना अनुसार राज्य में किसानों की एक लाख एकड़ भूमि को सेम की समस्या से निजात दिलाई जाएगी, ताकि किसान अपनी भूमि पर आसानी से फसलों की बिजाई कर सकें।

गोशालाओं में 2021-22 के दौरान 1200 किलोवॉट क्षमता के सौर ऊर्जा सयंत्र लगाए जाएंगे। बजट के मुताबिक 330 गोशालाओं में 1991 किलोवाट की संचयी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

'म्हारा देस हरियाणा'

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा'

विद्यार्थी करेंगे मृदा व पानी की जांच

किसानों और विज्ञान के विद्यार्थियों में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

के महत्त्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, विज्ञान के विद्यार्थियों को मृदा व पानी के नमूनों की जांच तथा उन्हें एक उद्यमी के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की गई है। पहले चरण में, वर्ष 2020-21 के दौरान मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु कुल 115 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों का चयन किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान स्कूलों/कॉलेजों/तकनीकी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में लगभग 125 मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। क्षारीय और लवणीय मृदा के उपचार हेतु योजना में किसानों की भागीदारी के लिए एक नया पोर्टल स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में कम से कम एक लाख एकड़ भूमि सुधार का प्रस्ताव है।

उद्यमिता को बढ़ावा

कृषि उत्पाद संगठनों की स्थापना और इसके तंत्र का विस्तार करना सरकार की एक और प्राथमिकता है। सरकार का मार्च, 2021 तक 500 किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य है जिसके विरूद्ध 486 किसान उत्पादक संगठन बनाए जा चुके है और मार्च, 2022 तक 1,000 किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जाएंगे। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फसल समूह विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

दस जिला क्षेत्र में 24 घंटे बिजली

'म्हारा गाँव जगमग गाँव' योजना के सुखद परिणाम आने लगे हैं। प्रदेश के 5080 गाँवों को कवर करने वाले 1261 फीडरों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के अधीन लाया जा चुका है। इन तरह 10 जिलों नामतः पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा और फतेहाबाद के शत-प्रतिशत गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। बजट में बिजली के लिए 7,089 करोड़ रुपए और अक्षय ऊर्जा के लिए 270 करोड़ की राशि का आबंटन किया गया है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान ऐसी 6,000 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें, 12 वॉट की 5,000 एलईटी सोलर स्ट्रीट लाइटें और सीसीटीवी कैमरा वाली 1,000 हाई मास्ट एलईडी सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। इन प्रयासों के तहत राज्य ने 'जैव ऊर्जा नीति' भी लागू की है।

खेल प्रतिभाएं तराशने पर फोकस

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खेल अवसंरचना विकसित करने, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने, छोटी उम्र से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करके उन्हें तराशने, खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने और विभिन्न युवा विकास कार्यक्रम लागू करने की मंशा से 'सभी के लिए खेल' का विजन पेश किया है।

खेल विभाग के लिए 394 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। प्रदेश में सरकारी और निजी स्कूलों में कुल 297 खेल नर्सरियां चल रही है। वैज्ञानिक प्रशिक्षण, खेल के दौरान लगने वाली चोट के उपचार और शीघ्र स्वस्थ लाभ के उद्देश्य से, हरियाणा में चार पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई है। एक राज्य स्तरीय पुनर्वास केंद्र पंचकूला में स्थापित किया जाएगा, जबकि मंडल स्तर के चार केंद्र रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और हिसार में प्रस्तावित हैं। अम्बाला कैंट स्थित वार हीरोज मैमोरियल स्टेडियम में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल और फुटबॉल ग्राउंड निर्माणाधीन है।

आगामी 'खेलो इण्डिया यूथ गेम्स-2021' के दृष्टिगत ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पंचकूला में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के नए मैदान बनाने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021', की मेजबानी हरियाणा करेगा। इनमें पांच स्वदेशी खेलों सहित 25 खेल स्पर्धाएं होंगी और देशभर से 10,000 से अधिक खिलाड़ियों और अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है।

राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में चयनित खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि देने की घोषणा की है, ताकि वे बेहतर आहार, नवीनतम प्रशिक्षण सुविधाएं और खेल उपकरण हासिल कर सके।

शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसें

मकसद से शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना में प्रदेश में सकल लागत मॉडल पर 124 पूर्णतः इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। वर्ष 2021-22 के बजट में परिवहन विभाग के लिए 2408 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनके अलावा बीएस-6 उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने वाली 800 मानक गैर-एसी बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा, किलोमीटर स्कीम के तहत किराए पर ली गई 536 बसों का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। इस तरह, जल्द ही हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की कुल संख्या 5,000 से अधिक हो जाएगी। साथ ही, प्रदेश में 54 वोल्वो मर्सिडीज सुपर लग्जरी एसी बसों 18 सुपर लग्जरी एसी मल्टी-एक्सल बसों का संचालन भी किया जा रहा है।

पर्यावरण प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों से बचाने के

जल ही जीवन है

- बजट अनुमान 2021-22 में 'जल जीवन मिशन कार्यक्रम' के तहत 1.65 लाख घरों में नल के माध्यम से जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- इस कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी घरों में नल के माध्यम से जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान सरकार ने इस कार्य को केवल वर्ष 2022 तक ही पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।
- हरियाणा में लगभग 31.05 लाख ग्रामीण परिवार है, जिनमें से जनवरी, 2021 तक 26.19 लाख (84.34 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों को जलापूर्ति कनेक्शन प्रदान किए जा चुके है।
- ग्रामीण संवर्धन जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत, गांवों में जलापूर्ति का स्तर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55-70 लिटर तक बढ़ाने के लिए मौजूदा जलापूर्ति सुविधाओं में सुधार तथा इन्हें मज़बूत किया जा रहा है।
- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए, नाबार्ड से भी धनराशि ली जा रही है।
- वर्ष 2020-21 में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 1,003.50 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाएं प्रगति पर है तथा वर्ष 2020-21 में रेवाड़ी, नारनौल और जींद में 129.10 करोड़ रुपए लागत की 3 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
- सरकार ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति 135 लिटर तक बढ़ाने, सीवरेज प्रणाली बिछाने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना के लिए महाग्राम योजना शुरू की है।

- बजट अनुमान 2021-22 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 3,402 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया।

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना' भी लागू की है। गाय व भैंस के दूध के लिए सहकारी दुग्ध उत्पादकों को पांच रुपए प्रति लिटर की दर से सब्सिडी सीधे बैंक खातों में दी जा रही है।

रेवाड़ी जिला में 32 नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं जिनको पंचायत आईटी सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगी। साथ ही पंचायत इस नॉलेज सेंटर में ग्रामीणों के लिए किताबों व न्यूजपेपर की व्यवस्था भी कर सकेंगी।

जैविक खेती से मिला रोज़गार

संगीता शर्मा

कृषि विज्ञान के नए आयाम और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनओं के चलते युवाओं का खेती की ओर रुझान बढ़ने लगा है। वे प्राइवेट नौकरियों की बजाय खेती में रोज़गार की नई संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। रेवाड़ी जिला के कंवाली गांव के 31 वर्षीय प्रगतिशील किसान यशपाल ने गारमेंट्स काम का काम छोड़कर खेती को अपनाया है। वे बारहमासी सब्जियों की खेती करते हैं। उन्हें सब्ज़ी एक्सपो 2020 में गाजर की खेती में हरियाणा में पहला स्थान पाने पर कृषि मंत्री, हरियाणा व इज़रायल के कृषि विशेषज्ञों द्वारा सम्मानित किया गया। वही, किसान दिवस के अवसर पर 23 दिसंबर, 2020 को प्रगतिशील किसान अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।

यशपाल ने वर्ष 2014 में अपनी तीन एकड़ ज़मीन पर परंपरागत फसलों से खेती शुरू की थी। एक साल बाद सब्जी की खेती करना शुरू कर दिया व वर्ष 2016 में लीज पर ज़मीन लेकर 12 एकड़ तक बढ़ाया। वर्ष 2018 में 25 एकड़ तक ले आए। आज उनके पास 25 से 40 तक लेबर हर रोज़ काम करते हैं।

जैविक खेती से मुनाफ़ा

यशपाल का कहना है कि जैविक खेती आज के समय की मांग है और कोरोना काल से जैविक सब्ज़ी व फलों की मांग अधिक बढ़ गई है। इसलिए हम इस खेती को अपनाकर बाज़ार के हिसाब से अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं। जैविक खेती में देसी खाद, केंचुआ खाद व देसी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। इन्हें घर में आसानी से बना सकते हैं। किसानों को एक तिहाई ज़मीन पर जैविक खेती करनी चाहिए जिसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जा सकता है।

फसल विविधिकरण को अपनाया

यशपाल कृषि में मिश्रित खेती, बैंबू स्टैकिंग, टपका सिंचाई, लोटरनल, मल्चिंग, पैकहाऊस, प्याज का भंडारण, रिटेल व थोक का काम करते हैं व जैविक उत्पादन, सब्ज़ी की ग्रेडिंग, बॉक्स पैकिंग, सिड प्रोसेसिंग, सब्जियों का भंडारण व प्रोसेसिंग, नर्सरी भी तैयार करते हैं। किसानों के लिए कोल्ड स्टोर का काम भी पूरा होने पर है व केंचुआ खाद व पशुपालन भी करते हैं। वह सीडलेस पीले रंग के तरबूज की खेती भी करते है। वह फफूंदीनाशक, कीटनाशक, बैक्टिरियानाशक, पोषक तत्व स्वयं तैयार करते हैं। उनका किसान उत्पादक संगठन 'डहिना' है इसमें 250 से 300 किसान जुड़े हैं। वह व्हाट्स अप ग्रुप 'एक्टिव फार्मर ग्रुप' के द्वारा हर रोज़ किसानों को सब्ज़ी व फलदार व अनाज की खेती में आने वाली समस्याओं को अवगत करवाते हैं। पूरी टीम मिलकर काम करती है और सलाहकार, खेती विशेषज्ञ व वैज्ञानिक उचित समाधान करते हैं। किसानों को सरकारी अनुदान प्राप्त कराते हैं व समय-समय पर किसानों के खेतों पर जाकर जैविक खेती, टपका सिंचाई, सरकारी प्रयोजनाओं व वैज्ञानिक तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं।

सब्जियों की मार्केटिंग सुविधा

वह 11 लाख रुपए की लागत से रिटेल वैन भी तैयार कर रहे हैं। जिसमें एसी केबिन बनाए जा रहे हैं और इसमें लगभग 11 क्विंटल सब्ज़ियों को रखकर अलग-अलग जाकर बेचा जाएगा। इसके अतिरिक्त वह रेवाड़ी, कोसली, पटौदी व गुरुग्राम की मंडी में भी अपनी सब्जियों की बिक्री करते हैं। इसके अलावा लोग खेतों से भी सब्ज़ियों को खरीदकर ले जाते हैं। डेयरी फार्मिंग करने की भी उनकी योजना है ताकि अधिक मात्रा में देसी खाद खुद तैयार कर सकें। वह कृषि रसायन एवं उर्वरक का बावल कृषि विश्वविद्यालय से डिप्लोमा भी कर रहे है, ताकि खेती से संबंधित अधिक ज्ञान हासिल कर सकें।

किसानों को मिली मार्केटिंग की सुविधा

सिरसा के ऐलनाबाद के खारी सुरेरा गांव के प्रगतिशील किसान मनोज कुमार सिहाग किन्नू की खेती से बाग-बाग हो रहे हैं। वह पहले पारंपरिक खेती कपास, गेहूं, बाजरा, ज्वार, चने की खेती करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना ध्यान किन्नू की खेती की ओर केंद्रित किया और धीरे-धीरे इस खेती में विस्तार करते गये। आलम यह है कि अब उनके गांव व आस-पास के पांच गांवों में अन्य किसानों ने किन्नू व मालटा की खेती करनी शुरू कर दी है। इस समय लगभग 1,500 एकड़ में किन्नू व मालटा की खेती हो रही है। उन्होंने किसानों को मार्केटिंग व अन्य सुविधा प्रदान करने के पहले बागवानी विभाग हरियाणा के सहयोग से खारी सुरेरा किसान उत्पादक संगठन का गठन किया, जिसमें 240 के करीब किसान शामिल हैं। उसके बाद बागवानी विभाग हरियाणा की लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (स्फैक) योजना के अंतर्गत 75 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ उठाकर पैक हाउस तैयार किया है।

सरकार से मिला अनुदान

किसान उत्पादक संगठन के सीईओ मनोज ने बताया कि जनवरी माह में इंटीग्रेटिड पैक हाउस तैयार किया था, हालांकि अभी कुछ काम अधूरा है। मगर किसानों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए पैक हाउस शुरू कर दिया है। एक एकड़ में बने पैक हाउस की लागत 3.37 करोड़ रुपए है, जबकि विभाग से 2.85 करोड़ का अनुदान मिला है। पैक हाउस की मशीनें अहमदाबाद से खरीदी हैं। उनका कहना है कि सरकार के अनुदान की वज़ह से वह पैक हाउस तैयार कर पाए हैं। इसमें किन्नू व मालटा की ग्रेडिंग, वैक्सिंग व पैकेजिंग सही तरीके से होती है। इससे किसानों को उच्च दाम मिलते हैं और साथ ही मार्केटिंग की सुविधा मिलती है। जबकि पहले किसान जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, दिल्ली, चंडीगढ़ व लुधियाना में अपने फल बेचते थे। कई ठेकेदार व एजेंट उनके खेतों में पहुंच जाते थे, जहां उन्हें उचित दाम नहीं मिलता था।

पैक हाउस किसानों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। इस पैक हाउस के माध्यम से लगभग 200-250 श्रमिकों को रोज़गार भी मिला है। जबकि 20 नियमित कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया कि अभी किन्नू का मौसम खत्म हो चुका है और दूसरे फलों व सब्ज़ियों की ग्रेडिंग, वैक्सिंग व पैकिंग शुरू हो जाएगी। दूसरे राज्यों से जिन फलों को हम खरीदकर लाते हैं, उनकी भी पैक हाउस में ग्रेडिंग, वैक्सिंग व पैकिंग की सुविधा मिलेगी।

बंपर पैदावार

मनोज ने बताया कि उनका गांव राजस्थान बॉर्डर से लगता है और उनके पास लगभग 35 एकड़ ज़मीन है। जिसमें 30 प्रतिशत ज़मीन में पानी लगता है और बाकी ज़मीन में रेत के टीले व उबड़-खाबड़ ज़मीन थी। फ़सल को बारिश के पानी पर निर्भर होना पड़ता था। वर्ष 2007 बागवानी विभाग, हरियाणा की राष्ट्रीय बागवानी मिशन की योजना के तहत अनुदान का लाभ उठाकर टपका सिंचाई और कम्युनिटी वाटर टैंक लगाए। जिससे ज़मीन को समतल व उपजाऊ बनाया। पहले मात्र 12 एकड़ ज़मीन में पारंपरिक खेती करते थे। धीरे-धीरे अथक प्रयास व मेहनत के चलते 25 एकड़ ज़मीन पर किन्नू की खेती करनी शुरू कर दी। तीन-चार साल बाद जब पेड़ ने फल देना शुरू किया तो इंटरक्रॉपिंग बंद कर दी। किन्नू से आमदनी होनी शुरू हो गई। मनोज ने बताया कि हमारी देखा-देखी गांव के अन्य लोगों ने किन्नू व मालटा की खेती करनी शुरू कर दी। क्योंकि वहां बालू मिट्टी है और इस खेती में पानी का प्रयोग भी कम होता है। वातावरण भी इस फल के लिए अनुकूल है। इसमें अच्छी किस्म व पैदावार के हिसाब से किसान को एक एकड़ में एक से दो लाख रुपए की आमदनी हो जाती है।

मनोज बताते हैं कि पैक हाउस बनने से समूह के किसानों व अन्य किसानों और आस-पास के राज्य के किसानों को भी फ़ायदा होगा। उन्हें किन्नू व मालटा की ग्रेडिंग, वैक्सिंग और पेकिंग करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उन्होंने डेढ़ रुपए प्रति किलो की दर से ये सब काम किए। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से शुरू हुए पैक हाउस में मार्च के पहले सप्ताह तक 1400 टन किन्नू डिस्पेच किए गए। इफ्को और हर्षना ग्रुप की मदद से उनकी फ़सल की बिक्री आसान हो गई और दाम भी अच्छे मिले। उन्होंने बताया कि इस बार किन्नू की बंपर फसल थी और किसानों को इसे बेचने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ा।

फसलों की खरीद के लिए अवश्य कराएं रजिस्ट्रेशन

किसान रबी सीजन की फसलों के लिए 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। फसलों का रजिस्ट्रेशन नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर करवाया जा सकता है। किसान पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण करवाकर अपनी फसल को सुविधापूर्वक बेच सकता है।

फसलों की सरकारी खरीद एवं कृषि विभाग की सभी स्कीमों का लाभ लेने के लिए किसानों द्वारा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यदि किसी खेत में कोई भी फसल नहीं बोई गई है तो उसका ब्यौरा भी पोर्टल पर किसान अवश्य दें। कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा किसान अपने स्वयं के मोबाइल से भी पंजीकरण करवा सकते हैं।

कहां होगा रजिस्ट्रेशन : परिवार पहचान पत्र को 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' के लिए भी अनिवार्य किया गया है। किसान अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन fasal.haryana.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान इस पोर्टल से किसानों को काफी फायदा पहुंचा था । किसानों के मोबाइल पर इस पोर्टल के जरिए ही मैसेज आता था, कि उन्हे अपना गेहूं और सरसों आदि को लेकर मंडी में किस दिन किस समय आना है।

रजिस्ट्रेशन के लिए ये जरुरी : रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी है, फसल से संबंधित जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस से मिलेगी। जमीन की जानकारी के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड के नकल की कॉपी, खसरा नंबर देख कर भरना होगा। फसल के नाम, किस्म और बुआई का समय मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भरना होगा । बैंक पासबुक की कॉपी भी लगानी होगी, ताकि किसी भी स्कीम का लाभ सीधे खाते में भेजा जा सके।

रजिस्ट्रेशन के तीन फायदे :

1. खाद, बीज, लोन एवं कृषि उपकरणों की सब्सिडी समय पर उपलब्ध होगी ।
2. फसल की बिजाई-कटाई का समय और मंडी संबंधित जानकारियां मिलेंगी ।
3. प्राकृतिक आपदा के बाद सही समय पर सहायता मिल सकेगी, क्योंकि आपकी फसलों का ब्यौरा पहले से ही इस पोर्टल पर दर्ज होगा।

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 'स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट' के बिना पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विवरण अब विभाग के पोर्टल पर 'मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम' (एमआईएस) में अपडेट किया जा सकेगा।

प्रदेश में 5,080 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में 40 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों को बिजली रेट में सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

महिला सम्मान- सशक्तिकरण का मान

महिलाओं को राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। लिंगानुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सिरसा, भिवानी और सोनीपत जिलों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया। इन पुरस्कारों के लिए पांच लाख, तीन लाख और दो लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार इन जिलों के उपायुक्तों को प्रदान किया गया।

राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रमशः नूह, महेंद्रगढ़ और पंचकुला को दिया गया। पुरस्कार स्वरूप 2 लाख, एक लाख और 50 हजार रुपए की राशि दी गई। इन जिलों के उपायुक्तों ने ये पुरस्कार प्राप्त किये। खेल, सामाजिक कार्य और कर्मचारी वर्ग में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भी 38 महिलाओं को सम्मानित किया गया।

कुमारी सुमेधा धानी और डॉ. प्रियंका सोनी को 'इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार' प्रदान किया गया। आशा को 'कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार' और भगवती देवी यादव को 'लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार' प्रदान किया। इसके अलावा खेलों, सामाजिक क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण और आंगनबाड़ी वर्करों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

500 मॉडल क्रेच होंगे स्थापित

अभी तक प्रदेश में महिलाएं सहायता के लिए हेल्पलाइन

नंबर 181 पर काल कर सकती थीं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए व्हाट्सएप नंबर की भी शुरुआत की। इमरजेंसी में प्रदेश की महिलाएं 9478913181 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिकायत कर सकती हैं।

महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने कई एमओयू साइन किए। मॉडल क्रेच के समझौते के साथ ही बचपन बचाओ अभियान के लिए कैलाश सत्यार्थी के एनजीओ से समझौता किया गया।

धापो ताई कर रहीं बेटियों को बचाने के लिए प्रेरित

झज्जर जिले में धापो ताई लोगों को घर-घर जाकर बेटियों को बचाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। जिले में अब धापो ताई की मुहिम के साथ 25 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धापो ताई के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात भी की और नन्हे धापो ताई की मुहिम को पूरे प्रदेश में चलाने का आग्रह किया।

हरियाणा में अनाथ बच्चों (ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं।) को संरक्षण और आश्रय देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 'हरि हर योजना' की शुरुआत की। जिन अनाथ बच्चों ने स्कूली शिक्षा पूरी कर ली, वे 25 वर्ष की आयु तक एक्स-ग्रेसिया के आधार पर ग्रुप सी और डी सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। यदि बच्चा स्नातक पूरा करता है तो उन्हें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत ग्रुप ए और बी की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा।

- संवाद ब्यूरो

ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी

महिलाओं ने अब घर परिवार की हदूद से बाहर निकलकर आकाश नापना शुरू कर दिया है। देश- प्रदेश, समाज, शहर व गांव के विकास में उनकी अहम भूमिका दिख रही है। हरियाणा की महिलाओं में यह जागरूकता अपेक्षाकृत अधिक है। यह संभव हुआ है प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण संबंधी नीतियों की वजह से। भाजपा-जजपा सरकार की ओर से ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी तय की गई है।

पंचायतों का हालीय कार्यकाल खत्म हो चुका है। आगामी चुनाव की तिथि की घोषणा होनी है। अब अधिक महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अपना भाग्य अजमाएंगी और गांवों के विकास के लिए ठोस कदम उठाएंगी। इस कानून से महिलाएं कितनी सशक्त होंगी और गांव की क्या सूरत बदलेगी। इस विषय पर कुछ महिला प्रतिनिधियों से चर्चा की।

चौपाल में आने लगी महिलाएं

पलवल जिला परिषद की प्रतिनिधि चमेली देवी राजनीतिक विज्ञान में एमए और एचआर में एमबीए किया है। उन्होंने हर क्षेत्र में विकास कार्य किए और गैर सरकारी संगठन से जुड़कर भी बहुत अच्छे काम किए हैं। पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत भागीदारी पर उन्होंने कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा।

वह महिलाओं की उच्च शिक्षा पर विशेष अहमियत देती हैं, ताकि महिलाएं राजनीति व पंचायती राज संस्थाओं में अपनी कुशल भागीदारी दिखाएं, न कि पुरुषों का सहारा लें। उन्होंने कहा कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक भावनात्मक होती हैं और ईमानदारी के साथ कार्य करती हैं। उन्होंने गांव में जब से महिला चौपाल बनाई है तब से महिलाएं चौपाल में आकर खुलकर बात करने लगी हैं।

कामकाज में पारदर्शिता आएगी

फतेहाबाद जिला परिषद की प्रतिनिधि गीता रानी का कहना है कि महिलाओं का पंचायती राज

संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण होने से महिलाएं और अधिक हौसले से चुनाव में भाग लेंगी और अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक होती हैं और सही निर्णय ले पाती हैं। उन्होंने कहा महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक ईमानदार होती हैं, इसलिए कामकाज में पारदर्शिता आएगी।

गांवों का होगा अधिक विकास

पलवल के हसनपुर ब्लॉक के भंडौली गांव की प्रतिनिधि उर्मिला ने पहली बार सरपंच के चुनाव पर आठ प्रतिद्वंदियों को हरा कर जीत हासिल की थी। उन्होंने बताया कि गांव में अनेक विकास कार्य किए। जल प्रबंधन एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा। मेधावी विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार व साइकिल वितरित की गई। स्कूलों में डेस्क और आर.ओ का प्रबंध किया। गांव में हर जाति के लिए चौपाल और वृद्धाश्रम भी बनवाए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की एक अनूठी योजना के तहत उनके गांव को फाइव स्टार का दर्जा मिला है। इसके तहत पुरस्कार हासिल किया व कुछ अन्य पुरस्कार भी जीते। बेटी के जन्म पर कुआं पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 50 प्रतिशत भागीदारी होने से महिलाएं चुनाव में बढ़चढ़कर भाग लेंगी। महिलाएं अब पुरुषों से कम नहीं हैं।

पंचायत चुनाव में सम-विषम संख्या के आधार पर महिला एवं पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। जिस गांव में महिला सरपंच निर्वाचित होगी, अगली योजना में उस गांव में पुरुष सरपंच होगा। यह कानून प्रदेश की महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार करेगा और उन्हें सशक्त करेगा। भविष्य में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में यह नियम लागू होगा। प्रत्येक गांव को सम-विषम संख्या के आधार पर कोड दिए जाएंगे। पहली बार में सम क्रम वाले गांवों में सरपंच महिला रहेंगी और अगली बार विषम क्रम संख्या वाले गांवों में महिला सरपंच बनेंगी। इस तरह हर दस वर्ष में से पांच वर्ष हरियाणा के हर गांव में महिला सरपंच होंगी। आरक्षित पदों पर भी यह नियम लागू होगा और उनमें भी सम-विषम संख्या के आधार पर पद आरक्षित होंगे। यही नहीं, ग्राम पंचायत के पंचों के विषय में भी यही प्रक्रिया रखी जाएगी और 50 फीसदी पंचों के पद महिलाओं के लिए रहेंगे।

पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले से है। इसके बावजूद पिछली बार 42 फीसदी महिलाएं चुनकर आई। यह व्यवस्था ग्राम पंचायतों से आगे बढ़कर जिला परिषद और ब्लॉक पंचायत समिति में भी लागू होगी। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों और चेयरमैन के पदों के लिए भी ऑड-ईवन का फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। पंचायती राज एक्ट में इस महत्त्वपूर्ण बदलाव के बाद हरियाणा में पंचायती राजतंत्र में महिलाओं की 50 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। इस व्यवस्था के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों और अन्य सीटों के लिए अलग-अलग समूह माने जाएंगे और इन समूहों में महिला आरक्षण लागू किया जाएगा।

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

बेड़िझक आती हैं महिलाएं

कैथल के चंदाना गांव की प्रतिनिधि बिमला स्नातक हैं। वे कहती है पंचायतों में 50 प्रतिशत भागीदारी होने से गांव का अधिक विकास होगा। उनके सरपंच बनने के बाद गांव के लिंगानुपात में सुधार हुआ है। गांव में दस चौपालें बनाई गई तथा गली व सड़कों की मरम्मत का भी बेहतरीन कार्य किया गया। तालाब व घाट साफ करवाए गए। उन्होंने बताया कि वह गांव व जिला स्तर की प्रत्येक बैठक व प्रशिक्षण में भाग लेती हैं और गांव के विकास कार्य स्वयं करवाती हैं।

- संगीता शर्मा

हॉकी इंडिया के तत्वाधान में भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप में शाहबाद की 18 लड़कियां चयनित हुई हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह ने इन खिलाड़ियों के लिए 2 लाख 75 हजार रुपए देने की घोषणा की।

प्रदेश में चालू आबकारी-वर्ष के तहत पिछले वर्ष जहां कुल 6,361 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था वहीं 4 मार्च 2021 तक 6,214 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ, जबकि यह आबकारी-वर्ष 19 मई 2021 तक रहेगा।

रंगों का पर्व होली

होली बसंत का पर्व है। सावन के बाद फागुन माह में पूरी सृष्टि में नया जीवन संचारित हो रहा होता है। मानव का तन-मन भी इससे अछूता नहीं रहता। अंतर्मन से भाव उमड़ते हैं कि क्यों न सारे बंधन तोड़कर प्रकृति के अनुकूल बह लिया जाए। अपनों को गले लगा लिया जाए, संबंधों में नए रंग भर दिए जाएं। भावनाओं का यही रेला होली का रंग है। ऐसा रंग जिस दिल में उठता है वह सौभाग्यशाली है, वह प्रकृति के करीब है। ऐसे में खुद को और अपने संबंधियों को रंगों से सराबोर करने में जरा सा संकोच नहीं करना चाहिए।

रंगों के उल्लास के अलावा होली के पर्व को मनाने के लिये बहुत ही पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उत्तर पूर्व भारत में होलिका दहन को भगवान कृष्ण द्वारा राक्षसी पूतना के वध दिवस के रूप में जोड़कर, पूतना दहने के रूप में मनाया जाता है तो दक्षिण भारत में मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने कामदेव को तीसरा नेत्र खोल भस्म कर दिया था और उनकी राख को अपने शरीर पर मल कर नृत्य किया था।

होली के उपलक्ष्य में अनेक सांस्कृतिक एवं लोक चेतना से जुड़े कार्यक्रम होते हैं। घूमर एक राजस्थानी कार्यक्रम है, उसमें लोग मस्त हो जाते हैं। चंदन का तिलक और ठंडाई के साथ सामूहिक भोज इस त्यौहार को गरिमामय छवि प्रदान करते हैं। देर रात तक चंग की धुंकार, घूमर, डांडिया नृत्य और विभिन्न क्षेत्रों की गायन मंडलियां अपने प्रदर्शन से रात बढ़ने के साथ-साथ अपनी मस्ती और खुशी को बढ़ाते हैं।

मथुरा और वृन्दावन में होली की भव्य छटाएं देखने को मिलती हैं। बसन्तोत्सव के आगमन के साथ ही वृन्दावन के वातावरण में एक अद्भुत मस्ती का समावेश होने लगता है, बसन्त का भी उत्सव यहां बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्रीकृष्ण की भक्ति में सराबोर होकर होली का रंगभरा और रंगीनी भरा त्यौहार मनाना एक विलक्षण अनुभव है।

होली के दिन हम सभी को स्नेह और सम्मान का, प्यार और मोहब्बत का, मैत्री और समरसता का ऐसा शमां बांधना चाहिए जिसकी बिसात पर मानव कुछ नया करने को प्रेरित हो सके। उत्सव चेतना का स्वभाव है और होली चेतना का उत्सव है। जो जितना अधिक स्वयं के द्वारा स्वयं को आनन्दित महसूस करता है, उसके जीवन में उतने ही रंगों से छटाएं भर जाती हैं।

होली एक पवित्र पर्व है। इसमें सब तुच्छ के भेद भाव मिट जाते हैं। जीवन में प्रसन्नता, हर्षोल्लास तथा आनंद का रंग बिखर जाए, सब एक दूसरे के लिए कामना करते हैं। इस पर्व पर सभी को कोई न बुरी आदत त्यागने का संकल्प लेना चाहिए तथा एक-दूसरे के साथ मिलकर चलने की शपथ लेनी चाहिए।

-मनोज प्रभाकर

सुंडाना का फाग

रोहतक जिला के गांव सुंडाना की होली काफी प्रसिद्ध है। होली से अगले रोज यानी फाग के दिन यहां का उत्सव रंग रंगीला व मस्ती भरा होता है। इस उत्सव का आनंद लेने के लिए न केवल पूरा गांव बल्कि गांव के रिश्तेदार पहले दिन व गुहांड के लोग दिन के दिन आ जाते हैं।

करीब बीस हजार की आबादी वाले गांव के भराण पाने में एक प्रमुख चौक है जिसे फलसा बोलते हैं। फाग के दिन फलसे को सजाया जाता है। काफी बड़े इस चौक के चारों ओर रंग-बिरंगी झालर बांधी जाती है। उस पर हजारों गुब्बारे भी सजाए जाते हैं। उस दिन इस चौक की साफ-सफाई करवाई जाती है। खेलों से हल्की मिट्टी लाकर यहां बिछाई जाती है। चौक के बीच में दो बड़े कढाहे रखे जाते हैं जिनमें साफ पानी भरा जाता है। पानी में किसी प्रकार का रंग या तेल नहीं होता। बिलकुल स्वच्छ पानी। फलसे के चारों कोनों पर चार ढोल बजाने वाले खड़े होते हैं। ये ढोल सुबह दस बजे से लेकर तीन बजे तक बजते हैं।

होली के दिन यानी फाग से एक दिन पूर्व घरों से श्रद्धा अनुसार कुछ चंदा एकत्र किया जाता है। जो राशि एकत्र होती है उसकी मिठाइयां खरीदी जाती हैं। मिठाइयां उन महिलाओं को फाग वाले दिन की शाम को खेल के बाद घर भिजवाई जाती हैं जिन महिलाओं ने फलसे पर फाग में हिस्सा लिया था। खेल में महिलाओं के लिए शर्त होती है कि वे अपने कोलड़े साधारण कपड़े के बनाएंगी तथा पुरुषों को हिदायत होती है कि वे अपने हाथ में कोई लकडी या डंडा नहीं रखेंगे। गुलाल लगाने की प्रक्रिया होली के दिन या फाग को सुबह निपटा ली जाती है।

स्थानीय युवकों द्वारा लाऊडस्पीकर पर पूरे फाग की कमेंटरी सुनाई जाती है। जैसे 'रामफल की बहू न सूरजे की कड़ में घणा कसूता कोलड़ा सेक दिया यै। सुरजा माड़ा सा मुहं बणाके भाज लिया। भाज लिया- भाज लिया और वो फेर पकड़ लिया। ओ तेरी की, एक और कोलड़ा पिंडियां पै सेक दिया पाले की बहू नै।'

दुलेंडी का यह पूरा खेल गांव की एक कमेटी की ओर से आयोजित किया जाता है। इस पूरे कार्यक्रम की खासियत यह है फाग के इस खेल में गांव की छत्तीस बिरादरी की महिलाएं व पुरुष भाग लेते हैं। तमाम ग्रामीणों का भाईचारा व मेलजोल उमंग भरा होता है, देखने व सुनने लायक होता है। पूरा साल दिलों में जो हल्की-फुल्की कड़वाहट होती है वह इस फलसे के पानी में धुल जाती है। आपसी संबंधों में नया रंग भर जाता है। फाल्गुन की मस्ती सिर चढ़कर बोलने लगती है।

लोकनाट्य कला-सांग

लोक संगीत, नाटक, सांग आज भी हरियाणा में मनोरंजन का लोकप्रिय माध्यम है। यह अन्य नाट्यशैलियों की अपेक्षा अधिक सशक्त लोकमंच माध्यम है। सांग में अभिनय, संवाद, नृत्य-संगीत,गायन कथा, भक्तिभाव, आध्यात्मिकता इत्यादि अनेक तत्वों का सम्मिश्रण है। यह हरियाणवी जीवन दर्शन का द्योतक एवं लोक संस्कृति का परिचायक भी है। प्रदेश के संस्कार, रीति-रिवाज, मान्यताएँ, आदर्श अथवा लोक जीवन का कोई भी आयाम सांग में अछूता नहीं रहता।

'सांग' शब्द का अर्थ है-'स्वांग भरना'यानी विभिन्न वेशभूषाओं में पात्र की ज्यों की त्यों नकल करना। यहाँ तक कि पुरुष स्त्री की वेशभूषा पहन मंच पर अभिनय करते हैं।

'सांग' न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि लोक कल्याण के कार्यों के लिए धनराशि जुटाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सांग मंडली के माध्यम से दान के रूप में धन इकट्ठा करने का प्रचलन है। दान धनराशि का एक निर्धारित भाग मंडली अपने पारिश्रमिक रूप में रख कर शेष भाग स्कूल, धर्मशाला, मंदिर, तालाब आदि के निर्माण कार्यों में दे देती है। यह धर्म परायणता का अनूठा उदाहरण है।

हरियाणा में सांग कब शुरू हुआ इसके बारे भिन्न - भिन्न मत हैं। सांग मंचन के लिए किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। बिना पर्दों, शृंगार खुले मैदान, गांव के चौराहे ,चौपाल पर बड़े तख्तों के मंच पर सांग का कार्यक्रम आसानी से हो जाता है। सांग की सफलता कलाकारों के कौशल पर निर्भर करती है। पांच - छह घंटे तक चलने वाले इस आयोजन में प्रायः बीस से तीस कलाकार भाग लेते हैं। सभी कलाकार पुरुष होते हैं। महिला की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं।

सांग में न लाउडस्पीकर और न ही इसका कोई प्रचार - प्रसार किया जाता। बस मौखिक प्रचार के माध्यम से दूर-दूर तक खबर फैल जाती है।

सांग आरंभ होने से एक घंटा पहले सांगियों के सहयोगी साथी मंच पर हारमोनियम, नगारा, ढोलक सारंगी, अलगोजा, बीन, चिमटा, बांसुरी, एकतारा इत्यादि वाद्ययंत्र बजाना शुरू कर देते है। गुरु के मंच पर पधारते ही सब कलाकार चरण स्पर्श कर उसका आशीर्वाद लेते हैं तथा ज्ञान की देवी (भवानी) की वंदना से सांग आरंभ करते हैं।

आई री भवानी वार कर मेरे घाट का परदा खोल,
रसना पर वास कर भाई शुद्ध शब्द मुख बोल।

लगभग दो सौ साल पहले किशनलाल भाट ने अपनी सांग मंडली बना कर इस लोक रंगमंच शैली की नींव रखी थी। उस समय नायक-नायिका के पीछे घूम-घूम कर साज बजाते थे। प.लखमी चंद के शिष्य प.मांगेराम की निम्नलिखित पंक्तियों से सांग परंपरा का परिचय मिलता है-

' हरियाणा की कहानी सुण ल्यो दो सौ साल की।
कई किस्म की हवा चाल्यी नई चाल की।
सिसाना निवासी बाजे भगत तथा सुनारियाँ वासी जमुवा मीर पंडित लख्मीचंद के समकालीन थे। बाजे भगत और पंडित लख्मीचंद दोनों ही सर्वाधिक चर्चित हरियाणवी कवि और सांगी रहे हैं। मांगेराम ने भाषा पर पकड़ तथा मुहावरों के प्रयोग में अपने गुरु लखमीचन्द को भी पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने सांग कला को मजबूती प्रदान करने के लिए 'हरियाणा गंधर्व सभा' का गठन किया परन्तु 16 नवंबर, 1967 ई को उनकी मृत्यु के बाद ही यह सभा भी खत्म हो गयी।

वर्तमान में सांग प्रेमियों में महावीर का नाम अतीव लोकप्रिय हैं। सांग का मूल आधार लोकगाथाएं, पौराणिक कथाएं तथा राजा महाराजाओं के किस्से-कहानियां ही रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग सांग देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। लोकसंस्कृति की इस अमूल्य नाट्य शैली को समयानुरूप परिवर्तन के साथ - साथ जीवंत रखने की भी आवश्यकता है।

प्रस्तुतिः सुरेंद्र बांसल

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए, कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com